

आतंकवाद की अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ उमारतन यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर—अर्थशास्त्र, विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय (झाँसी)

शोध सारांश

आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव किसी एक क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर पड़ता है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो जन, धन, भौतिक और प्राकृतिक सम्पदा पर पड़ता है। जिससे जन-धन, भौतिक और प्राकृतिक सम्पदा की हानि होती है, उससे उस राष्ट्र का आर्थिक विकास कई वर्षों पीछे चला जाता है। आतंकवादियों के द्वारा ऐसे-ऐसे अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिससे मानवीय क्षति के साथ उत्पादन, आय-व्यय, रोजगर की गति धीमी हो जाती है। जो एक देश की आर्थिक विकास गति को खत्म कर कई वर्ष उसे पीछे कर देती है। आतंकवादी संगठनों का निशाना कोई सरकार या देश नहीं है उसे तो हिंसात्मक ढंग से कार्य कर व्यक्तियों में भय व्याप्त करके अपने स्वार्थों को पूरा करना है—अब चाहे वो राजनैतिक हो जिससे देश या क्षेत्र पर अपना शासन करना चाहते हैं या किसी भी देश की भौतिक सम्पदा हो या प्राकृतिक क्षेत्रों का अपने कब्जे में लेना चाहते हों या जनता में भय व्याप्त करके सार्वजनिक हिंसा या हत्याओं का सहारा लेते हैं इससे नुकसान तो देश का है जिसके विकास में आतंकवाद अवरोध उत्पन्न करता है।

Keywords : आतंकवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतन्त्र, स्वतंत्रता, प्रभाव

आज आतंकवाद विश्व की गम्भीरतम समस्या हो गई है। आतंकवाद के कारण सामान्य से लेकर विशेष व्यक्ति तक कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा से सम्बन्धित है जो अपने विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति हिंसा से करना चाहती है। आतंकवादी विचारधारा किसी भी देश के न्याय द्वारा स्थापित सत्ता को हिंसक तरीकों से चुनौती देकर वहाँ की अर्थव्यवस्था का विखण्डन करती है। अनेक देशों के प्राचीन इतिहास के पन्नों में आतंकवाद विभिन्न प्रकार से परिभाषित हो चुका है— यह शब्द आज नया नहीं है बल्कि यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद ने हमेशा राष्ट्रों को क्षति पहुँचाने की कोशिश की है। प्राचीन समय से आतंकवाद दुनिया भर के

सभी समाजों के लोकतन्त्र और स्वतंत्रता के आदर्शों के मार्ग में बाधा बना हुआ है। आतंकवाद ने भारतीय अस्तित्व की प्रगति एवं मानवीय विकास को कड़ी चुनौती दी है। भारत में आतंकवाद के पनपने के आर्थिक, जातीय, राजनैतिक और सामाजिक कारण है। देश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, धार्मिक कटटरता आदि आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं। आतंकवाद ने दुनिया के अनेक राष्ट्रों में विकृतियों को जन्म दिया है आतंकवाद की बढ़ोत्तरी का एक सामाजिक कारण यह भी है कि वर्तमान संदर्भों में पूरी दुनिया में नैतिक मूल्यों में हास होता जा रहा है इसके साथ ही साथ लोगों के मन में भौतिकवाद के चलते राष्ट्रीयता की भावना में कमी दिखायी पड़ रही

है। व्यक्तिगत हित एवं लिप्सा के कारण राष्ट्रीय भावनाओं की अवहेलना की जा रही है। उपर्युक्त कारणों के समवेत रूप से आतंकवाद की बृद्धि में अपनी भूमिका निभायी है। जिससे मानवीय मूल्यों का ह्यास हुआ है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही मध्य एशिया में उत्तरी काकेशस के क्षेत्र में इस्लामी आतंकवाद ने पैर जमाना आरंभ कर दिया है। पूरे उत्तरी काकेशस क्षेत्र को स्वतंत्र इस्लामी राज्य में रूपांतरित करना उनका मुख्य लक्ष्य है। इस तरह चीन में मुस्लिम आतंकवादियों का प्रकोप जारी है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिन च्यांग में वर्ष सन् 1988 ई0 से यह आंदोलन चल रहा है। श्रीलंका का आतंकवादी संघर्ष छिपा हुआ नहीं है। “वहाँ लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल-इलम (लिटटे) के नेतृत्व में छापामार लड़ाई भी चल चुकी है। अल्जीरिया, सूडान और मिश्र जैसे देश हजारों वर्ष पुरानी अरब संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब ये भी पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की भट्टी में झुलस रहे हैं। आतंकवाद का यह भयावह साया तुर्की, जोर्डन, लीबिया, ईराक आदि देशों में भी है।”

भारत में आतंकवाद-आतंकवाद सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह तो भारत की पहचान को समाप्त कर देने का षड्यंत्र भी है।” मोहम्मद बिनकासिम, महमूद गजनबी, गौरी, बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा लगभग चौदह सौ वर्षों से भारत पर आक्रमण कर हमारी पहचान ही नष्ट करने के प्रयासों का ही वर्तमान रूप है। गत दो दशक से शुरू हुआ “जिहादी आतंकवाद”। इन बीसेएक वर्षों में हजारों निर्दोष नागरिक व सेना और सुरक्षा बलों के जवानों अधिकारियों की नृशंस हत्या की जा चुकी है। राष्ट्र की सम्प्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को नष्ट करने के पुष्ट प्रयास हुए हैं। 13 दिसम्बर सन् 2001 ई0 को भारत की संसद पर जिहादी हमले को लगभग

20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान पोषित सशस्त्र जिहादी आतंकवादी सारे सुरक्षा प्रबंधों को धत्ता बताकर हमारी संसद में घुस आये और संसद परिसर रक्त रंजित हो गया। इसके बाद तो इन आतंकवादियों ने भारत के बड़े-बड़े नगरों को चुन-चुन कर निशाना बनाया। हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों दिल्ली के चहल-पहल भरे बजारों, मुम्बई लोकल ट्रेनों में, श्रृंखलावद्व विस्फोटों से होते हुये यह आग 26/11 के बीभत्स और पूरे देश को चौकाने वाले मुम्बई काण्ड तक पहुँच गई। इन सभी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद इनका दाबा करने वाले इस्लामी संगठन लस्कर-ए-तैयबा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, जमात-उद-दाबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मुहम्मद, अल-कायदा सामने आते हैं। ये आतंकवादी संगठन खुलेआम इस बात की अनेक बार अपने संदेशों व धमकियों में घोषणा कर चुके हैं कि दारूल हरव (मुस्लिम अल्प संख्या वाली भारत की धरती) को दारूल इस्लाम (पूर्णतः इस्लामी विश्वास वाली धरती) में बदलने के लिए ये जिहाद है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद पुर्णतः पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। वे कश्मीर को भारत में विलय को स्वीकार करना नहीं चाहते तथा कश्मीर में अल्लावादी गतिविधियों को सहायता प्रदान कर उसे भारत से अलग कर देना चाहते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छाया युद्ध और आतंकवाद है। हजरत बल दरगाह पर कब्जा संसद और कश्मीर विधान सभा पर हमला भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। आतंकवाद के विकास के कारण के रूप में यह भी तर्क दिया जाता है कि अरब जनसंख्या का विस्तार विश्व के अन्य क्षेत्रों में (सीमित संसाधनों को देखते हुए (पेट्रोल) करने के उद्देश्य से इस्लाम के कट्टर अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। अरब जगत आतंकवादी संगठनों का एक आश्रय स्थल (हब) बनता जा रहा है।

आज आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना है। अब आतंकी संगठनों के पास विभिन्न प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक उपलब्ध हैं। नाभिकीय, रासायनिक, एवं जैविक हथियार भी आतंकवादियों की पहुँच की परिधि में हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी भयावह चुनौती से निपटने के लिये दुनिया के सभी छोटे-बड़े देशों को एक जुट हो जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनौती किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। यदि आतंकवाद को जन्म देने वाले एवं इसको बढ़ावा देने वाले कारणों पर समुचित ध्यान दिया जो और समाज में असंतोष को जन्म देने वाले कारणों का निराकरण समुचित रूप से किया जाए तो कोई भी देश आतंकवाद की भयानक विभीषिका को न केवल नियंत्रित कर सकते हैं वरन् उसका उन्मूलन भी समय रहते कर भी सकता है भारत में आतंकवाद के अच्छे विशेषज्ञों की कमी नहीं है। आवश्यकता है तो सही नतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन करने की। सत्ता एवं विपक्ष के बीच सम्वादहीनता समाप्त करने की। महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं का समुचित निराकरण कर आतंकवाद की जड़ों को कमज़ोर किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. शर्मा, सुरेश के.व.उषा शर्मा (सम्पादक) (1999), "सोसायटी, इकोनोमी एण्ड कल्चर ऑफ कश्मीर," दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. खण्डेला, मानचन्द्र (2002), "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद," आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूर्स, जयपुर।

3. लल्लन (2003), "राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा," सारिका ऑफसेट प्रेस, मेरठ।
4. चन्द्र, महेश व वी.के. पुरी (2005), "रीजनल प्लानिंग इन इंडिया," एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. त्रिपाठी, मधुसूदन (2008), "राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद," ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. यादव, डॉ० वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) (2010), "नई सहस्राब्दी का आतंकवाद—संघर्ष के बदलते प्रतिमान," ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
7. यादव, डॉ० वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) (2010), "बदलते परिदृश्य में नई सहस्राब्दी का भारत," ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
8. दत्त, रुद्र एण्ड के.पी.एम. सुन्दरम (2010), "भारतीय अर्थव्यवस्था," एस. चॉद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
9. त्रिपाठी, राशि (2010), "आतंकवाद—मानवाधिकार : चुनौती और समाधान," "बदलते परिदृश्य में नई सहस्राब्दी का भारत," यादव वीरेन्द्र सिंह (स), ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
10. सुंदर, नंदिनी (2011), "इन्टर्निंग इनसर्जेन्ट पोपुलेशन्स : द बैरीड हिस्ट्रीज ऑफ इण्डियन डेमोक्रेसी," इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 5, 2011
11. कुरियन, एन.जे. (2000), "वाइडनिंग रीजनल डिस्पेरिटीज इन इंडिया," इकोनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली, फरवरी 12–18, 2000
12. सिंह, नौनिहाल (1989), "द वर्ल्ड ऑफ टैररिज्म," साउथ एशियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।